देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 23.04.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- बदरीनाथ धाम के कपाट आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक ढंग से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुले।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समयसीमा को लेकर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।
- केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 अधिसूचित किया। यह पहली मई से प्रभावी होगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 124 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

बदरीनाथ धाम कपाट

चमोली ज़िले में स्थित बदरीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक ढंग से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर देशभर से हजारों श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। इसके साथ ही उत्तराखंड के चारों धाम अब श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं।

कपाट खुलने के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ धाम को भव्य रूप से सजाया गया है। जैसे ही धाम के कपाट खुले, पूरा धाम जय बदरी विशाल के जयकारों से गूंज उठा। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और सेना के बैंड की धुनों के बीच श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा गया। इस अवसर पर 'महाभिषेक पूजा' मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से कराई और देश–प्रदेश की समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में सहयोग की अपील भी की।

गौरतलब है कि इससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट कल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को ही खुल चुके हैं। चारधाम के कपाट हर वर्ष गर्मियों में खोले जाते हैं और सर्दियों की शुरुआत के साथ बंद कर दिए जाते हैं।

आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से किरन कृषाली

समीक्षा

इससे पहले कल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के बीआरओ गेस्ट हाउस में बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कार्यों की प्रगति, तकनीकी पहलुओं और आगामी योजनाओं की जानकारी दी गई।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मास्टर प्लान के अंतर्गत आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, यात्री सुविधाओं के विस्तार, आवागमन व्यवस्था में सुधार और आधुनिक सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य धाम को भव्य, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त तीर्थस्थल के रूप में विकसित करना है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुव्यवस्थित अनुभव मिल सके।

उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने, गुणवत्ता बनाए रखने और निर्माण कार्यों में उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजनाओं में पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धाम में विकसित की जा रही सभी सुविधाओं में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। यातायात, आवास, स्वच्छता, पेयजल और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर समय पर लागू करने के निर्देश भी दिए गए।

स्थलीय निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न स्थलों का दौरा कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समयसीमा का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कार्य जिलाधिकारी की निगरानी में तय समयसीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना आस्था और राज्य की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही कार्यों की नियमित निगरानी और समय–समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बीआरओ बाईपास रोड, लूप रोड, लेक, आईएसबीटी, सिविक एमिनिटी भवन, टीआईसीसी और अराइवल प्लाजा जैसे पूर्ण हो चुके कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने इन परियोजनाओं के शीघ्र हस्तांतरण के निर्देश दिए, ताकि इनका लाभ तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को जल्द मिल सके।

मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त तीर्थ अनुभव प्रदान करना है।

अधिसूचना

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन संबंधी नियम–2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह पहली मई से लागू होगा। इन नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करना, लोगों की सुरक्षा करना, वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखना, समन्वित प्रवर्तन को सक्षम बनाना और उपयोगकर्ता के अधिकारों को बनाए रखना है।

वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 124 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं के माध्यम से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने, पेयजल और बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को भी गति मिलेगी।

स्वीकृत योजनाओं में देहरादून में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना, अल्मोड़ा में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, न्यू कैंट मार्ग के चौड़ीकरण से जुड़े कार्य, पौड़ी जिला कारागार में आवासीय भवन निर्माण और रामनगर में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा मसूरी और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रों में पुल और सड़क निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।

हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के तहत गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों और पुलों के पुनरुद्धार के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में पार्क, तालाब और ऐतिहासिक भवनों के सौंदर्यीकरण के साथ ही टिहरी, खटीमा और अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है।

स्वच्छता समीक्षा

राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सचिवालय स्थित आपदा निवारण एवं प्रबंधन केंद्र में स्वच्छता कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

देहरादून में आयोजित बैठक में उन्होंने स्वच्छता कर्मचारियों के जोखिम भरे कार्य को देखते हुए उनका बीमा कवर 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने और उनका वेतन उपनल तथा पीआरडी कर्मचारियों के

समान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मचारी समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके हितों और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

बैठक में निकायों में कार्यरत मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्वच्छता कर्मचारियों को श्रम विभाग के अंतर्गत कुशल और अर्ध–कुशल श्रेणी में शामिल करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक के दौरान सीवर लाइन की सफाई के लिए रोबोटिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल संस्थान को रोबोट का प्रदर्शन कराने को कहा गया। नगर निगम देहरादून द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर शीघ्र स्वीकृति के लिए अनुरोध करने और स्वच्छता कर्मचारियों के एक लाख रुपये तक के ऋण माफी के संबंध में भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।